



राहुल गांधी को 5, सुनहरी बाग, बंगला अलॉट हुआ

यह नया बंगला सोनिया गांधी के बंगले से व नये संसद भवन से एक मिनट कार ड्राइव की दूरी पर है

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। अब राहुल गांधी का पाता बदल गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत से उहैं कैविनट मंडी के दर्जा प्राप्त है तथा इसलिये अब वे टाइप-8 आवास के लिये अधिकृत हैं।

लोकसभा की हाउसिंग कमेटी में आवास के रूप में उहैं 5 सुनहरी बाग रोड बंगला आवंटित किया गया। राहुल ने अपनी तक आवास को स्वीकार किया लिखित सहमति नहीं दी है, हालाँकि उनके सुझाकर्मी नये आवास में पहुँच गये हैं तथा उसकुठा से भरे मीडिया को बहाए हैं।

आज विपक्ष की दूरी पर है तथा इनी ही दूरी इस संसद भवन से उहैं कैविनट के नेता के रूप में उहैं बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निवहन करता है।

संसद की नई इमारत में भी राहुल

- राहुल को नये संसद भवन में एक ऑफिस भी अलॉट हुआ है, विपक्ष के नेता की हैसियत से।
- राहुल का यह ऑफिस इण्डिया गढ़बन्धन के नेताओं की आवा-जाही का केन्द्र बन गया है, तथा वरिष्ठ नेतागण, जैसे शरद पवार भी वहां प्रायः देखे जाते हैं।
- अब गांधी परिवार की सदस्या प्रियंका गांधी ही एक प्राइवेट मकान में रह रही है, क्योंकि उनकी सुरक्षा हटा देने के बाद, उनको नया बंगला अलॉट करना आवश्यक नहीं है।
- चर्चाओं के अनुसार, राहुल गांधी द्वारा वायनाड की संसदीय सीट से इस्तीफा देने के बाद, प्रियंका गांधी वहां से सेवनावाही और वहां से उनके तीनों बड़े नेता प्रबल अंशभावना है, फिर, गांधी परिवार के तीनों बड़े नेता अपने अपने सरकारी निवास में हक्क से रहने लगे।

को उनके कक्ष दिया गया है, जो विपक्षी में प्रायः दिखाई देते हैं। एल.ओ.पी. की अधिकांश मीटिंग में भी इसी कक्ष में होती है। लिंगले चंद्र रोज से गहल यहाँ रहने के लिए 10 जनपथ चले गए। अब वे वहाँ से इस बंगले में शिफ्ट होंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वे उन्हें भाषण के मुख्य बिन्दुओं के बारे में भी बता रहे हैं तथा बाटे के उन बारीक बिन्दुओं पर भी चर्चा कर रही हैं, जिन पर विशेष जार दिया जाना जरूरी है।

यद दिला दें कि जब राहुल पहली बार सासद बाथे, उस समय उहैंने 12 तुगलक लेने को अपना घर बनाया था। यह बैंगला उन्होंने सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं को मैदानजर रखते हुए आवंटित किया गया था।

लेकिन जब ऊजरात उच्च न्यायालय के आदेश ने उन्हें डिस्ट्रिक्टिवार्क कर दिया था तो उनके पास उस बैंगले को खाली करने का उपरिकास भेजा गया था। उस समय राहुल उच्चवार अदालत में अपील कर रहे थे, इसके बावजूद उहैंने बैंगला खाली कर दिया था। जातव्य है कि उहैंने अपील की थी तथा जात गये थे। लेकिन उन्हें कोई बैंगला आवंटित नहीं किया गया तथा वे अपनी भाइयों के बोतानी ही पर्याप्त नहीं रहे। इसके बारे में बोतानी ही पर्याप्त नहीं रहे। राहुल ने उन्होंने अपनी साथी को खाली कर दिया था। जातव्य है कि उहैंने अपील की जारी रखी गई है।

एल.ओ.पी. को उनके बारे में यहाँ लिंगले चंद्र रोज से गहल यहाँ रहने के लिए 10 जनपथ चले गए। अब वे वहाँ से इस बंगले में शिफ्ट होंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रियंका गांधी ने इज़राइली प्रधानमंत्री को “बर्बर” कहा

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। युद्ध की तात्परी जैसे फिलीसीयों ने अपील के प्रयास के तहत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गांधी पर बांध के लिए इज़राइल की कठोर निंदा की। गांधी पर इज़राइल का हमला दस माह से चल रहा है और अब इसमें 40,000 लोग मरे जा चुके हैं। प्रियंका ने विश्व समुदाय से अपील की है कि वे इस नसहार के लिए

सुप्रीम कोर्ट ने यू.पी. सरकार पर लगे “स्टे” की अवधि बढ़ाई

यू.पी. सरकार का निर्देश था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों को अपने मालिक व कर्मचारियों के नाम, प्रतिष्ठान पर प्रमुखता से डिस्प्ले करने होंगे

-सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अन्तरिम स्टेट को हटाने से इकार कर दिया जो उसने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले खान-पान के भोजनालयों के बारे में यू.पी. सरकार के इकावड़ यात्रा के गते में आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के गते में अपील के लिए भोजनालयों के बारे में आदेश

कोर्ट ने इस बात को रोका किया था कि अपील में इसमें जारी जाने में नसहार में योग्यता नहीं रही। इसके बावजूद उहैंने बैंगला खाली कर दिया था। जातव्य है कि उहैंने अपील की थी तथा जात गये थे। लेकिन उन्हें कोई बैंगला आवंटित करने की तैयारी कर रहे थे, इसके बावजूद उहैंने बैंगला खाली कर दिया था। जातव्य है कि उहैंने अपील की जारी रखी गई है।

कोर्ट ने इस बात को रोका किया था कि अपील में जारी जाने में नसहार में योग्यता नहीं रही। इसके बावजूद उहैंने अपील की जारी रखी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश पर, 22 जुलाई को स्टे लगाया था, जो 26 जुलाई तक लागू रहना था, पर, आज 26 जुलाई को यह “स्टे” अगली तारीख, यानि 5 अगस्त तक जारी रखने के आदेश दिये।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अभी यू.पी. सरकार द्वारा इस मसले पर प्रस्तुत जवाब को पढ़ नहीं पाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पर यह भी स्पष्टीकरण दिया कि अगर इन ढार्वा, थियों के मालिक व स्वामी तक व्याप्त होती है अपना नाम दुकान पर प्रमुखता से डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोई आपत्ति नहीं होगी।

मुकुल रोहती ने यू.पी. सरकार की तथा अधिकारी मनु सिंघवी ने यू.पी. सरकार के आदेश के खिलाफ तुण्डल कांग्रेस की तारीख 5 अगस्त तक अन्तरिम स्टे को बढ़ा दिया।

हालांकि, बैंगले ने स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक आधार पर दुकानों के बाहर कांवड़ यात्रा के दौरान उनके मार्ग में अपने नाम लिखे जाते हों तो 22 जुलाई आने वाले ढार्वा तक तथा भोजनालयों के कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक में जोर पकड़ रहा केन्द्र बनाम राज्य का झगड़ा

नीट और ई.डी. के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सख्त रुख अपनाया

भारतवासी 58 देशों की वीज़ा प्रीयात्रा कर सकते हैं

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। पाकिस्तान का पासपोर्ट लगातार जीवंत वैध चीथे सबूत बना रहा है। यह जानकारी हैन्ती यापायेट इन्डिया की नवीनता जानकारी में दी गई है। पाकिस्तान के नामांकित किसी सिर्फ 33 देशों की ही

- कर्नाटक ने विधानसभा में नीट परीक्षा प्रणाली के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु भी दो बार ऐसा प्रस्ताव पारित कर चुका है।
- कर्नाटक में ई.डी. अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई है तथा आरोप लगाया गया है कि ई.डी. अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों को, मंत्री की ओर आवंटाचार के केस में फंसाने के लिए दबाव बनाने का अधिकारीयों के खिलाफ कर रहे हैं।

पहले ही दोबार कर चुका है और कर्नाटक ने भी घोषणा की है कि राज्य प्रशासन के विरोध करती रही है कि नीट के लागू सरकार अपने प्रदेश में मेडिकल कार्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट को खाली कर दिया गया है। जिसका तात्पर्य यह है कि नीट के लागू सरकार अपने प्रदेश में मेडिकल कार्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट को खाली कर दिया गया है।

यह कुछ वैसा ही है जैसा कि केन्द्र सरकार ने देश में मेडिकल कार्यक्रम के लिए नीट को खाली कर दिया है। उनका यह अधिकारी जीवंत लिया गया है। नीट के खिलाफ दो बार कर्नाटक ने देश में संसद सभा में संसदीय संस्करण के लिए नीट को खाली कर दिया है। नीट के खिलाफ दो बार कर्नाटक ने देश में संसद सभा में संसदीय संस्करण के लिए नीट को खाली कर दिया है।

</div

